The Tribune- 16- February-2023

Drive to clean Yamuna floodplains from today

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Delhi Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena will launch an intensive operation to clean the Yamuna floodplains, involving Territorial Army personnel on Thursday.

According to a statement issued by Raj Niwas, a 94-member company of the Territorial Army will be drafted to ensure ground level enforcement and monitoring of all untrapped drains and sub-drains that pollute the river. The second meeting of the

"High Level Committee (HLC) on Rejuvenation of River Yamuna", was held on Tuesday wherein the L-G reviewed the progress of works and the Action Taken Report (ATR) with regards to trapping of drains, de-silting of sewers, status of Sewage Treatment Plants (STPs) and Common Effluent Treatment Plants (CETPs), redevelopment of Yamuna Floodplains and penal action against water polluting industries for violation, among others.

The cleaning and rejuvenation work in the Yamuna and its floodplains has picked up within last one month, said the statement. In a meeting of the committee on Tuesday, the LG was informed by officials that 13 sub-drains of Najafgarh Drain were fully trapped and 3.03 km of trunk/peripheral sewer lines were completely desilted since January 20 when the panel met for the first time. In an inspection of 88 industrial units during the period, water and power connection of 12 polluting units were cut and a penalty of Rs 53 lakh was imposed. The officials informed the LG that so far, a 17-km stretch of Najafgarh Drain has been cleaned. Trapping of three untrapped major drains - Barapullah Drain, Maharani Bagh Drain, Mori Gate Drain - will be completed by September 2023. This will check the flow of 48.14 MGD of sewage into the Yamuna, officials informed.

Under the Interceptor Sewer Projects (ISP), 76 untrapped sub-drains — 44 sub-drains of Najafgarh Drain, two falling into Shahdara Drain and 30 sub-drains of Supplementary Drains — will be completely trapped by September 2023, the officials assured the LG.

Amar Ujala- 16- February-2023

यमुना में प्रदूषण रोकने के लिए प्रादेशिक सेना की तैनाती

सफाई के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति की बैठक, एलजी की पहल पर 29 साल बाद कायाकल्प का सपना होगा पूरा

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। यमुना की सफाई के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की दूसरी बैठक हुई। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीवर की डी सिल्टिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीटीपी) समेत नालों की स्थिति, बाढ़ के मैदानों के पुनर्विकास और उद्योगों से होने वाले प्रदूषण पर शिकंजा कसने के लिए की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई।

सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की लगातार निगरानी के बावजूद पिछले 29 वर्षों से लंबित यमुना की सफाई और कायाकल्प की शुरुआत एलजी की पहल पर हुई है। यमुना के प्रदूषण को रोकने और निगरानी के लिए पहली बार प्रादेशिक सेना की तैनाती की जाएगी।

उच्चस्तरीय समिति की बैठक के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना बृहस्पतिवार को यमुना के बाढ़ के मैदानों के लिए गहन सफाई अभियान शुरू करेंगे। इसमें सभी क्षेत्रों के गणमान्य लोग शामिल होंगे। एलजी इस मौके पर पहली बार यमुना सफाई अभियान में प्रादेशिक सेना का मसौदा तैयार करेंगे। प्रादेशिक सेना की 94 सदस्यीय कंपनी यमुना को प्रदूषित करने वाले सभी नालों और उप-नालों की जमीनी स्तर पर निगरानी करेगी।

एलजी ने 15 दिन में मांगी रिपोर्ट : यमुना नदी के कायाकल्प के लिए एनजीटी के आदेश पर उच्चस्तरीय समिति गठित की गई। बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने नालों की देखरेख और स्वामित्व रखने वाली एजेंसियों(पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, डीडीए, डीजेबी, डीएसआईआईडीसी) को मौके पर जाकर निरीक्षण के बाद 15 दिनों के भीतर उन सभी अवैध उप-नालों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। अब तक यह सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है। बैठक में अधिकारियों ने एलजी को जानकारी दी कि नजफगढ़ ड्रेन के 13 उप नालों को फंसाने सहित 3.03 किलोमीटर के दायरे की सीवर लाइन को पूरी तरह गाद मुक्त कर दिया गया है।

परियोजना में कोताही बर्दाश्त नहीं : नालों को ट्रैप करने, सीवर लाइन से गाद निकालने, अनाधिकृत रिहायशी कॉलोनियों में सीवर नेटवर्क और जेजे क्लस्टर में ड्रेनेज संबंधित कार्यों की प्रगति और अगले 6 माह में सभी सभी प्रमुख उप नालों से होने वाले प्रदूषण को रोकने का काम पूरा कर लिया जाएगा। एलजी ने एजेंसियों को निर्धारित समय-सीमा में सख्ती से मानकों के मुताबिक कार्यों को पूरा करने को कहा। साथ ही चेतावनी दी कि परियोजना को लागू करने में किसी तरह की कोताही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

12 इकाइयों पर 55 लाख का जुर्माना

समिति की पहली बैठक के बाद 88 जल प्रदूषणकारी इकाइयों का निरीक्षण किया गया। इनमें प्रदूषण के लिए जिम्मेवार 12 इकाइयों के पानी और बिजली के कनेक्शन काटने सहित उनपर 53 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इस दौरान कार्यों की शुरुआत से पहले और बाद की वीडियो भी एलजी को प्रदर्शित की गई। अधिकारियों ने उपराज्यपाल को बताया कि अब तक नजफगढ़ नाले के 17 किलोमीटर हिस्से की सफाई की जा चुकी है और इनमें से 1.2 लाख घन मीटर गाद निकाला गया है।

सितंबर तक पूरे होंगे काम

- नजफगढ़ ड्रेन के 13 उप नाले पूरी तरह से ट्रैप किए गए
- बारापुला, महारानी बाग और मोरी गेट ड्रेन को ट्रैप करने का काम सितंबर तक पूरा किया जाएगा। इससे यमुना में प्रवाहित होने वाले 48.14 एमजीडी सीवेज की जांच की जाएगी।
- सितंबर तक पेरिफेरल सीवर लाइन की 200 किलोमीटर के दायरे को गाद मुक्त कर लिया जाएगा। 90 किलोमीटर की सीवर लाइनों को जून तक डी-सिल्ट किया जाएगा।
- नजफगढ़ ड्रेन के तिमारपुर से ख्याला तक 17 किलोमीटर की दूरी को साफ किया गया है।
- 573 कॉलोनियों में सीवर नेटवर्क डालने का काम चल रहा है। इनमें 264 कॉलोनियों में जून तक कार्य पूरा कर लिया जाएगा जबकि शेष 70 कॉलोनियों में सितंबर तक पूरा किया जाएगा।

Punjab Kesri- 16- February-2023

यमुना के बाढ़ क्षेत्रों की सफाई के लिए एलजी आज से शुरू करेंगे अभियान

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): यमुना के बाढ़ क्षेत्रों की सफाई के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा गुरुवार को एक गहन सफाई अभियान शुरू करेंगे। इस अभियान में प्रतिष्ठित व्यक्तित्व और समाज के सभी क्षेत्रों के लोग यमुना की सफाई में भाग लेंगे। उपराज्यपाल इस अवसर पर पहली बार यमुना सफाई अभियान में टेरिटोरियल आर्मी का ड्राफ्ट तैयार करेंगे। टेरिटोरियल आर्मी की यह 94 सदस्यीय कंपनी यमुना को प्रदूषित करने वाले सभी अनट्रेप्ड ड्रेन और सब ड्रेन की जमीनी स्तर पर निगरानी सुनिश्चित करेगी। यहां बता दें कि मंगलवार को उपराज्यपाल ने यमुना की सफाई को लेकर एनजीटी द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की दूसरी बैठक ली। इस दौरान एलजी ने यमुना का कायाकल्प गुणवत्ता से समझौता किए बगैर तय समय में पूरा करने को कहा है। साथ ही इस दिशा में तय लक्ष्यों को भी समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। राजनिवास में हुई इस बैठक में 20 जनवरी को हुई समिति की पहली बैठक में लिए गए निर्णयों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। एलजी ने अधिकारियों से कहा कि यमुना में गिरने वाले नालों की सफाई, सीवर लाइन से गाद निकालने, एसटीपी के निर्माण, सेप्टेज प्रबंधन आदि के लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा से पहले पूरा करना सुनिश्चित करें। इस बैठक में मुख्य सचिव, सिंचाई, वन एवं पर्यावरण, कृषि और वित्त विभागों के सचिव, केंद्रीय कृषि, पर्यावरण और जल शक्ति मंत्रालयों के सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक सहित अन्य हितधारक भी शामिल रहे। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने एक प्रेजेंटेशन भी दिया। मालूम हो कि उपराज्यपाल की अध्यक्षता में एनजीटी ने उच्च स्तरीय समिति का गठन नौ जनवरी को किया था। उन्होंने यमुना के मुख्य प्रदूषक नजफगढ़ नाले में बहते नालों से गाद निकालने और दोहन में अब तक के कार्यों पर संतोष व्यक्त किया और शाहदरा नाले में इसी तरह के प्रयासों को दोहराने के लिए भी कहा। सक्सेना ने एक बार फिर अधिकारियों से कहा कि हाथ में लिया गया कार्य कठिन है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। उन्होंने प्रतिबद्ध समय सीमा को बढ़ाए बिना मिशन मोड में निर्णयों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें प्रेरित भी किया। साथ ही यह भी कहा कि अधिकारियों की ओर से किसी भी तरह की कमी को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

गौरतलब है कि उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक में यमुना सफाई के लिए संबंधित विभागों में आठ मानकों पर छह महीने की कार्ययोजना तैयार करने पर सहमति बनी थी। इसमें सीवेज उपचार को बढ़ाना, अनधिकृत कालोनियों में सीवर नेटवर्क बिछाना और यमुना के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र को उसके मूल स्वरूप में बहाल करना भी शामिल है।